तीन साल में पीपीपी मॉडल से 105 से 120 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य

लखनऊ। दस खरब डालर की अर्थव्यवस्था में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है। प्रदेश सरकार कई सेक्टरों में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दे रही है। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार ने 2023-24 से 2027-28 तक 105 लाख करोड़ से 120 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पीपीपी मॉडल अपनाने के लिए कोर सेक्टर के साथ सक्षम सेक्टरों को किया गया चिह्नित

वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 279 अरब डॉलर थी, जिसे अगले पांच वर्ष में दस खरब डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अलग-अलग सेक्टरों को प्रमोट किया जा रहा है। कोर सेक्टरों में जहां कृषि, निर्माण, पर्यटन, आईटी और आईटीईएस शामिल हैं तो वहीं सक्षम सेक्टरों में शिक्षा व कौशल विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास को रखा गया है। वर्ष 2027-28 तक प्रदेश को दस खरब डॉलर अर्थव्यवस्था पहुंचाने के लिए न्यूनतम 105 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है। इसमें सरकारी हिस्सेदारी 12 से 16 लाख करोड़ के बीच रह सकती है। जबकि निजी हिस्सेदारी 93 से 108 लाख करोड़ रुपये तक हो सकती है। विभिन्न सेक्टरों में करीब दो लाख करोड़ के पीपीपी प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं या चल रहे हैं। ब्यूरो